

राजस्थान उच्च न्यायालय
जयपुर बेंच
एस.बी. आपराधिक अपील संख्या 5/1992

शिव प्रकाश, पुत्र श्री जगन नाथ, उम्र 27 वर्ष, निवासी बर्किया, पुलिस थाना अटरू, जिला बारां।

----अभियुक्त-अपीलकर्ता

बनाम

राजस्थान राज्य

----उत्तरदाता

याचिकाकर्ता(ओं)के लिए : श्री प्रणव पारीक
श्री अमन लोढा
उत्तरदाता(ओं)के लिए : श्री मानवेन्द्र सिंह, पीपी

जस्टिस अनूप कुमार ढांड

आरक्षित 10/10/2024
घोषित 19/10/2024
रिपोर्टयोग्य

आदेश

व्याख्या की सुविधा के लिए इस निर्णय को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया गया है: -

अनुक्रमणिका

I. तथ्यात्मक

मैट्रिक्स.....
.....2

II. पक्षों के वकील द्वारा
प्रस्तुतियाँ.....3

III. साक्ष्य का
विश्लेषण.....
.....5

IV. मुद्दे पर कानून.....
.....10

V. निष्कर्ष.....
.....19

1. इस अपील में सत्र प्रकरण संख्या 71/1990 में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संख्या 2, बारां (जिसे आगे "ट्रायल न्यायाधीश" कहा जाएगा) द्वारा पारित दिनांक 18.12.1991 के निर्णय की सत्यता पर प्रश्न उठाया गया है।
2. दिनांक 18.12.1991 को दिए गए विवादित निर्णय को पारित करते हुए, विद्वान ट्रायल जज ने अभियुक्त-अपीलकर्ता (जिसे आगे "अपीलकर्ता" कहा जाएगा) को धारा 376 आईपीसी के साथ धारा 511 आईपीसी के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया और उसे 500/- रुपये के जुर्माने के साथ पांच साल के कठोर कारावास (संक्षेप में "आरआई") की सजा सुनाई और जुर्माना अदा न करने पर छह महीने के साधारण कारावास (संक्षेप में "एसआई") की सजा सुनाई।

I. तथ्यात्मक मैट्रिक्स:

3. वर्तमान अपील के तथ्य इस प्रकार हैं:

3.1 कानून की यह कार्रवाई तब सामने आई जब अभियोक्ता (पीडब्लू-5) के पिता ने पुलिस स्टेशन बारां, जिला कोटा में एक प्राथमिकी (प्रत्यक्ष पी4) दर्ज कराई, जिसमें आरोप लगाया गया कि 07.02.1985 को शाम लगभग 4.30 बजे उनकी 5 वर्षीय बेटी "एस" रोती हुई आई और बताया कि किराएदार शिव प्रकाश (जिसे आगे "अपीलकर्ता" कहा जाएगा) ने उसके साथ बलात्कार किया है। जब शिकायतकर्ता शाम लगभग 7.00 बजे उनके घर आया, तो उनकी पत्नी ने उन्हें पूरी कहानी सुनाई और उसके बाद, वह अपनी बेटी को प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन ले गए।

3.2 इस रिपोर्ट पर, पुलिस स्टेशन, बारां, जिला कोटा में धारा 376 आईपीसी के तहत अपराध संख्या 24/1985 दर्ज किया गया और जांच के बाद, पुलिस ने धारा 376, 511 और 354 आईपीसी के तहत अपराधों के लिए अपीलकर्ता के खिलाफ आरोप पत्र प्रस्तुत किया।

3.3 निचली अदालत ने अपीलकर्ता के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अंतर्गत आरोप तय किए। अभियुक्त ने आरोपों से इनकार किया और मुकदमे की मांग की। इसके बाद, मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष ने अपने मामले के समर्थन में सात गवाहों से पूछताछ की और नौ दस्तावेज प्रस्तुत किए। इसके बाद, अपीलकर्ता का स्पष्टीकरण सीआरपीसी की धारा 313 के अंतर्गत दर्ज किया गया, जिसमें उसने घटना में अपनी संलिप्तता से इनकार किया और कहा कि रंजिश के कारण उसे झूठा फंसाया गया है, लेकिन बचाव पक्ष ने कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया।

3.4 दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, विद्वान ट्रायल जज ने दिनांक 18.12.1991 के निर्णय के तहत अपीलकर्ता को दोषी ठहराया और सजा सुनाई, जैसा कि ऊपर बताया गया है।

3.5 विवादित निर्णय से व्यथित और असंतुष्ट होकर, अपीलकर्ता ने धारा 374 सीआरपीसी के तहत यह अपील दायर करके इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

II. पक्षों के वकील द्वारा प्रस्तुतियाँ:

4. अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने दलील दी कि अभियोजन पक्ष का पूरा मामला अभियोक्ता- "एस" (पीडब्लू-1) की एकमात्र गवाही पर आधारित है और वह एक विश्वसनीय गवाह नहीं है। वकील ने दलील दी कि उसके बयानों में कई विरोधाभास हैं और बलात्कार के प्रयास के संबंध में उसके द्वारा बनाई गई कहानी विश्वसनीय नहीं है। वकील ने दलील दी कि कथित घटना घनी आबादी वाले क्षेत्र में हुई, लेकिन अभियोजन पक्ष द्वारा एक भी स्वतंत्र गवाह पेश नहीं किया गया। वकील ने दलील दी कि अभियोक्ता के बयानों के अनुसार, उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार किया गया था, लेकिन इस तरह के आरोप की पुष्टि उसकी मेडिकल जांच से नहीं होती है जब डॉ. पी. झंवर (पीडब्लू-6) द्वारा उसकी चोट की रिपोर्ट (एक्स-पी6) तैयार की गई थी। वकील ने दलील दी कि अभियोक्ता की चोट की रिपोर्ट (एक्स-पी6) के अनुसार, उसके शरीर पर हिंसा का कोई निशान नहीं था और उसकी योनिच्छद बरकरार और स्वस्थ पाई गई और उसमें कोई स्राव दिखाई नहीं दे रहा था। वकील ने कहा कि विश्लेषण के लिए उसका योनि से स्वाब लिया गया था और उसे विश्लेषण के लिए फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (संक्षेप में "एफएसएल") भेजा गया था। वकील ने कहा कि जब रासायनिक विश्लेषण प्रक्रिया आयोजित की गई थी, तो अभियोक्ता के योनि स्मीयर में वीर्य पाया गया था, जबकि वास्तव में अभियोक्ता का स्मीयर कभी एकत्र नहीं किया गया था। वकील ने कहा कि अभियोक्ता के योनि स्वाब के संबंध में कोई रिपोर्ट नहीं है, इसलिए, इन परिस्थितियों में, अभियोजन पक्ष उचित संदेह से परे अपीलकर्ता के खिलाफ अपना मामला साबित करने में विफल रहा है। वकील ने कहा कि जब अभियोक्ता से जिरह की गई थी, तो वह अपने संस्करण को कायम रखने में विफल रही, इसलिए, इन परिस्थितियों में, अपीलकर्ता आरोपित अपराधों से बरी होने के योग्य है। उनके तर्कों के समर्थन में, निर्मल प्रेमकुमार और अन्य बनाम के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित फैसले पर भरोसा रखा गया है। राज्य प्रतिनिधि पुलिस निरीक्षक द्वारा (आपराधिक अपील संख्या 1098/2024) 11.03.2024 को निर्णयित।

5. इसके विपरीत, विद्वान सरकारी अभियोजक ने अपीलकर्ता के वकील द्वारा की गई प्रार्थना का विरोध किया और कहा कि अपीलकर्ता द्वारा अभियोक्ता, जो कि 5 वर्ष की नाबालिग लड़की थी, के साथ बलात्कार का प्रयास किया गया था। वकील ने कहा कि बलात्कार के प्रयास के आरोपों की पुष्टि एफएसएल रिपोर्ट (एक्स-पी10) से हुई है, क्योंकि अभियोक्ता और अपीलकर्ता के अंतःवस्त्र से मानव वीर्य का पता चला था। वकील ने कहा कि अभियोक्ता के योनि स्मीयर में मानव वीर्य पाया गया था, इसलिए, इन परिस्थितियों में, अभियोजन पक्ष ने अपीलकर्ता के खिलाफ उचित संदेह से परे अपना मामला साबित कर दिया है और इस प्रकार, उसे 18.12.1991 के आक्षेपित फैसले के तहत विद्वान ट्रायल जज द्वारा सही रूप से दोषी ठहराया गया और सजा सुनाई गई है। वकील ने कहा कि इन परिस्थितियों में, इस न्यायालय के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

III. साक्ष्य का विश्लेषण:

6. बार में प्रस्तुत किए गए तर्कों को सुना और उन पर विचार किया तथा रिकार्ड पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया।

7. अपीलकर्ता के अपराध को प्रमाणित करने के लिए अभियोजन पक्ष ने सात गवाहों से पूछताछ की। अभियोक्ता पीडब्लू-1 "एस" घटना के समय 05 वर्ष की थी। उसने बताया कि अपीलकर्ता उसके घर में किरायेदार के रूप में रह रहा था। 07.02.1985 को शाम लगभग 4.30 बजे, अपीलकर्ता ने उसे अपने कमरे में बुलाया और उसे जबरदस्ती बिस्तर पर लिटा दिया, उसके अंतःवस्त्र उतार दिए और अपने गुप्तांग उसके गुप्तांगों से छूए और दबाए, जिससे उसका अंतःवस्त्र पानी (वीर्य) से गीला हो गया। उसने पूरी घटना अपनी माँ को बताई, जिन्होंने बाद में उसके पिता को यह बात बताई।

7.1 इस गवाह से अपीलकर्ता ने जिरह की, लेकिन उसने घटना का विवरण वैसे ही दिया जैसा घटना वाले दिन उसके साथ हुआ था। हालाँकि, उसके अदालती बयानों में थोड़ा सुधार हुआ था जो उसके पुलिस बयान (एक्स-डी1) में नहीं था और इसका कारण स्पष्ट था, क्योंकि घटना 07.02.1985 को हुई थी, जबकि अदालती बयान पाँच साल से भी ज़्यादा समय बाद, यानी 07.06.1990 को दर्ज किए गए थे।

8. पीडब्लू-2 बाबूलाल वह हेड कांस्टेबल है जिसने मामले की जब्त सामग्री के सीलबंद पैकेटों को मालखाने में जमा कराया था।

9. पीडब्लू-3 "के" अभियोक्ता की मां है और उसने कहा है कि पांच साल पहले दूसरे महीने में, वह खाना बना रही थी और लगभग 4:30 बजे शाम को उसकी बेटी रोती हुई आई और उसे बताया कि अपीलकर्ता ने अपने गुप्तांग उसके गुप्तांग में डाल दिए और उसने अपनी बेटी का गीला अंडरवियर देखा और जब उसका पति लगभग 7 बजे शाम को आया, तो उसने उसे पूरी घटना सुनाई।

10. अभियोक्ता-4 राम प्रसाद एक गवाह है जिसकी उपस्थिति में पुलिस ने अभियोक्ता के कपड़े प्र-पी1 के तहत जब्त किए थे और अपीलकर्ता के अंडरवियर भी प्र-पी2 के तहत जब्त किए थे और घटनास्थल का स्थल मानचित्र (प्र-पी3) तैयार किया था। जिरह में इस गवाह ने कहा है कि कपड़े घटना के अगले दिन जब्त किए गए थे।

11. पीडब्लू-5 "एस" अभियोक्ता का पिता है, जिसने एफआईआर में दिए गए बयान के समान ही बयान दिया है कि जब वह अपनी ड्यूटी के बाद घर वापस आया, तो उसकी पत्नी ने उसे पूरी घटना बताई, जैसा कि उसकी बेटी ने उसे बताया था। वह इस घटना से व्यथित था और उसके बाद उसने पुलिस स्टेशन, बारां में एफआईआर (एक्स-पी5) दर्ज करके पुलिस को मामले की सूचना दी।

11.1 इस गवाह के साथ-साथ अभियोजन पक्ष और उसकी मां से अपीलकर्ता द्वारा गहन पूछताछ की गई, लेकिन उनसे इस मामले में अपीलकर्ता को झूठे आरोप में फंसाने के कारण के बारे में एक भी पत्र नहीं पूछा गया।

12. पीडब्लू-6 डॉ. पी. झंवर चिकित्सा अधिकारी हैं, जिन्होंने अभियोक्ता की जांच की और उन्होंने कहा कि उन्हें अभियोक्ता के जननांगों में किसी वस्तु का प्रवेश नहीं मिला, लेकिन उन्होंने विश्लेषण के उद्देश्य से दो स्लाइड लीं। उसी दिन उन्होंने अपीलकर्ता का भी परीक्षण किया और पाया कि वह यौन संबंध बनाने में सक्षम है।

12.1 उन्होंने अभियोक्ता की मेडिकल रिपोर्ट प्र-पी6 और अपीलकर्ता की मेडिकल रिपोर्ट प्र-पी7 तैयार की, लेकिन अपीलकर्ता द्वारा अभियोक्ता की मेडिकल जांच के बारे में कोई जिरह नहीं की गई।

13. अंतिम गवाह पीडब्लू-7 रवि करण जाँच अधिकारी हैं जिन्होंने जाँच की, साक्ष्य एकत्र किए और अपीलकर्ता के विरुद्ध आरोप-पत्र प्रस्तुत किया। उन्होंने प्राथमिकी (प्रत्यक्ष-पी4) दर्ज की और गवाहों के बयान दर्ज किए, अपीलकर्ता को गिरफ्तारी ज्ञापन (प्रत्यक्ष-पी8) के माध्यम से गिरफ्तार किया और उन्होंने अपीलकर्ता

द्वारा घटनास्थल के बारे में अपने समक्ष प्रस्तुत किया गया प्रकटीकरण कथन (प्रत्यक्ष-पी9) तैयार किया। जिरह में, इस गवाह ने बताया कि जाँच के दौरान, अभियुक्त का एक धुला हुआ अंडरवियर जब्त किया गया था।

14. अभियोजन साक्ष्य बंद होने के बाद अपीलकर्ता के बयान धारा 313 सीआरपीसी के तहत दर्ज किए गए, जिसमें उसने घटना में अपनी भागीदारी से इनकार किया और कहा कि उसे दुश्मनी के कारण झूठा फंसाया गया है, लेकिन बचाव में कोई सबूत पेश नहीं किया गया।

15. अभियोजन पक्ष के गवाहों के साक्ष्य तथा एफएसएल द्वारा प्रस्तुत रासायनिक विश्लेषण रिपोर्ट (एक्स-पी10) के साथ आरोप की पुष्टि के आधार पर ट्रायल कोर्ट ने अभियोक्ता पर बलात्कार का प्रयास करने के अपराध के लिए अपीलकर्ता को दोषी पाया, जिसमें अभियोक्ता और अपीलकर्ता के अंतःवस्त्रों पर तथा अभियोक्ता के योनि स्मीयर में मानव वीर्य पाया गया था।

16. अभियोजन पक्ष का पूरा मामला बाल साक्षी पीडब्लू-1 "एस" के एकमात्र साक्ष्य पर आधारित है, जिसके साथ यह घटना घटी थी। इस न्यायालय ने उसके बयानों की सावधानीपूर्वक जाँच की है, जिसमें उसने स्पष्ट रूप से कहा है कि अपीलकर्ता ने उसे अपने कमरे में बुलाया और बिस्तर पर लिटा दिया, उसके और अपने कपड़े उतार दिए और अपने गुप्तांगों को उसके गुप्तांगों से छुआ और दबाया जिससे उसे दर्द हुआ और उसका अंडरवियर गीला हो गया। इस गवाह से अपीलकर्ता द्वारा जिरह की गई और पुलिस के समक्ष दर्ज किए गए उसके पहले के बयानों (एक्स.डी1) की तुलना में थोड़ा सुधार और विरोधाभास पाया गया। उसके बयान में थोड़ा विरोधाभास और सुधार स्पष्ट था क्योंकि जब घटना 07.02.1985 को हुई थी, तब यह बाल साक्षी 05 वर्ष की थी और जब 07.06.1990 को उसके बयान दर्ज किए गए, तब उसकी आयु 11 वर्ष थी। यद्यपि बयान घटना की तारीख से 05 वर्ष और 04 महीने बाद दर्ज किए गए थे, फिर भी इस गवाह के साक्ष्य में कोई बदलाव नहीं आया है।

16.1 कानून का यह स्थापित प्रस्ताव है कि बाल गवाह द्वारा दिए गए बयान के मूल्यांकन के संबंध में कानून का विश्लेषण करते समय, न्यायालय को इस तथ्य को ध्यान में रखना होगा कि बाल गवाह न्यायालय के तनावपूर्ण वातावरण में असुरक्षित और संवेदनशील होता है।

16.2 वर्तमान मामले में पीड़ित लड़की के बयानों को अन्य परिस्थितियों की पृष्ठभूमि में समझना, विश्लेषण करना और समझना होगा, जिनकी पुष्टि एफएसएल के वैज्ञानिक साक्ष्यों से की जानी है। इस प्रकार, केवल इसलिए कि पीड़िता ने वास्तविक हमले के बारे में कुछ नहीं बताया है, यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि

हमला हुआ ही नहीं था। उसकी कम उम्र और कमजोरियों को देखते हुए, उसके बयान को एफएसएल रिपोर्ट के आलोक में समझना होगा।

17. अभिलेखों में उपलब्ध साक्ष्यों के अनुसार, अभियुक्त ने पीड़िता को बिस्तर पर लिटा दिया और उसके तथा अपने कपड़े उतार दिए, फिर अपने गुप्तांगों को उसके गुप्तांगों में डालने की कोशिश की और खलित हो गया। मानव वीर्य पीड़िता और अपीलकर्ता, दोनों के अंतःवस्त्रों पर पाया गया, और अभियोक्ता के योनि-स्नान में भी। बचाव पक्ष द्वारा लंबी जिरह के बावजूद, घटना के बारे में उसका बयान नहीं बदला है। वास्तव में, बचाव पक्ष यह तर्क नहीं दे सका कि पाँच साल की उम्र के एक बच्चे ने अपीलकर्ता पर ऐसे आरोप क्यों लगाए। अपीलकर्ता यह तर्क देने में विफल रहा है कि वर्तमान मामले में उस पर झूठा मुकदमा क्यों चलाया गया है।

IV. इस मुद्दे पर कानूनः.

18. अब इस न्यायालय के समक्ष यह प्रश्न शेष है कि क्या धारा 376/511 आईपीसी के तहत अपराध बनता है या नहीं?

19. बलात्कार के प्रयास के अपराध के लिए, अभियोजन पक्ष को यह स्थापित करना होगा कि वह तैयारी के चरण से आगे बढ़ चुका है। केवल तैयारी और अपराध करने के वास्तविक प्रयास के बीच का अंतर मुख्यतः दृढ़ संकल्प की अधिकता में निहित है, जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **मदन लाल बनाम जम्मू और कश्मीर राज्य मामले में, जो एआईआर 1998 एससी 386** में दर्ज है, कहा है। पैरा 12 में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार टिप्पणी की: -

"अपराध करने की तैयारी और प्रयास के बीच का अंतर मुख्य रूप से दृढ़ संकल्प की अधिक डिग्री में निहित है और बलात्कार करने के प्रयास के अपराध को साबित करने के लिए जो आवश्यक है वह यह है कि अभियुक्त तैयारी की स्थिति से आगे बढ़ गया है।"

20. "प्रयास" क्या होता है, यह कानून और तथ्य का एक मिश्रित प्रश्न है जो मुख्यतः मामले की परिस्थितियों पर निर्भर करता है। "प्रयास" एक सटीक और सटीक परिभाषा देता है। मोटे तौर पर, सभी अपराध जिनमें सकारात्मक कार्य शामिल होते हैं, उनसे पहले कुछ गुप्त या प्रत्यक्ष आचरण होता है जिसे तीन चरणों में विभाजित किया जा सकता है। पहला चरण तब होता है जब अपराधी पहली बार अपराध करने का विचार या इरादा रखता है। दूसरे चरण में, वह इसे करने की तैयारी करता है। तीसरा चरण तब आता है जब अपराधी अपराध करने के लिए जानबूझकर प्रत्यक्ष कदम उठाता है। "अपराधी" होने के लिए ऐसे प्रत्यक्ष कार्य या कदम

का अपराध करने की दिशा में अंतिम से पहले का कार्य होना आवश्यक नहीं है। यह पर्याप्त है यदि ऐसा कार्य या कार्य जानबूझकर किए गए हों और लक्षित अपराध करने का स्पष्ट इरादा प्रकट करते हों, जो अपराध की परिणति के यथोचित रूप से निकट हों।

20.1 "प्रयास" करने के लिए, सबसे पहले, किसी विशेष अपराध को करने का इरादा होना चाहिए; दूसरे, कुछ ऐसा कार्य किया गया होगा जो अनिवार्य रूप से अपराध के लिए किया गया होगा और तीसरा, ऐसा कार्य इच्छित परिणाम के "निकट" होना चाहिए। निकटता का माप समय और कार्रवाई के संबंध में नहीं बल्कि अपराध करने के इरादे के संबंध में है। दूसरे शब्दों में, कार्य को अन्य तथ्यों और परिस्थितियों के साथ उचित निश्चितता के साथ प्रकट करना चाहिए और जरूरी नहीं कि अलग से, एक इरादे को, विशेष अपराध करने की महज इच्छा या उद्देश्य से अलग करके, प्रकट करना चाहिए, हालांकि कार्य अपने आप में ऐसे इरादे का केवल सूचक या संकेत हो सकता है, लेकिन यह होना चाहिए, अर्थात् यह इरादे का सूचक या संकेत होना चाहिए।

21. रेक्स बनाम लॉयड के मामले में (1836) 7 सी एंड पी 318 में रिपोर्ट की गई, लॉर्ड पैटरसन, जे. ने इस बिंदु पर क्या अभियुक्त का कृत्य बलात्कार करने के प्रयास के बराबर था, संक्षेप में निम्नानुसार माना:

“बलात्कार के इरादे से किए गए हमले के लिए अभियुक्त को दोषी ठहराने के लिए, आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि अभियुक्त ने, जब उसने अभियोक्ता को पकड़ा, न केवल उसके शरीर पर अपनी वासनाओं को तृप्त करना चाहा, बल्कि वह ऐसा हर हाल में और उसकी ओर से किसी भी प्रतिरोध के बावजूद भी करना चाहता था। हमारा मानना है कि इस देश में अभद्र हमलों को अक्सर बलात्कार के प्रयासों में, और उससे भी ज़्यादा बार बलात्कार में ही बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया जाता है; और हमारा मानना है कि बलात्कार के प्रयास के मामले में दोषसिद्धि तब तक नहीं होनी चाहिए, जब तक कि न्यायालय इस बात से संतुष्ट न हो जाए कि अभियुक्त का आचरण हर हाल में और हर प्रतिरोध के बावजूद अपनी वासनाओं को तृप्त करने के दृढ़ संकल्प को दर्शाता है। वर्तमान मामले में, चिकित्सीय साक्ष्य और शिकायतकर्ता द्वारा अलग-अलग समय पर दिए गए अलग-अलग बयानों को देखते हुए, हम उसके बयान पर पूरी तरह भरोसा करना असंभव पाते हैं; और, जहाँ तक उस पर की गई हिंसा की सीमा का सवाल है, उसके अपने बयान के अलावा कोई सबूत नहीं है। सत्र न्यायालय ने उसके इस आरोप पर विश्वास नहीं किया है कि प्रवेश हुआ था और परिणामस्वरूप अभियुक्त को बलात्कार का दोषी ठहराने से इनकार कर दिया है। हम शिकायतकर्ता के इस अप्रमाणित कथन पर कि अभियुक्त का आचरण बलात्कार के प्रयास के समान था, निष्कर्ष पर पहुँचने में हमें भी इसी तरह की हिचकिचाहट महसूस होती है। ऐसा लगता है कि उसे रोके जाने से पहले ही उसने ऐसा करना बंद कर दिया था; और यह दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं दिया गया है कि शिकायतकर्ता के शरीर पर हिंसा के निशान थे (जबकि सिविल सर्जन का साक्ष्य इसके विपरीत है), न ही यह कि शिकायतकर्ता या

अभियुक्त के कपड़ों पर कोई दाग था जिससे पता चलता कि अभियुक्त का अपराध किस हद तक बढ़ गया था।”

उस मामले में धारा 354 आईपीसी के तहत दोषसिद्धि हुई थी।

22. बलात्कार के प्रयास और अभद्र हमले के बीच का अंतर कभी-कभी बहुत ही कम होता है। पहले मामले में, अभियुक्त की ओर से कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे यह पता चले कि वह अभियुक्ता के साथ यौन संबंध बनाने जा रहा है। बलात्कार के प्रयास के अपराध के लिए अभियोजन पक्ष को यह स्थापित करना होगा कि वह तैयारी के चरण से आगे बढ़ चुका है। केवल तैयारी और अपराध करने के वास्तविक प्रयास के बीच का अंतर मुख्यतः दृढ़ संकल्प की अधिक मात्रा में निहित है।

23. इस न्यायालय ने **एआईआर (राजस्थान) 1967 (3) 149 में दर्ज सिद्ध बनाम राजस्थान राज्य** के मामले में, मामले पर विचार करते हुए, चाहे आईपीसी की धारा 376/511 के तहत अपराध का मामला पाया गया हो या नहीं, यह माना कि जहां लड़की को जबरन नग्न किया गया था, आरोपी ने उसके मजबूत प्रतिरोध के बावजूद उसके गुप्तांगों में पुरुष अंग डालने की कोशिश की, वह बलात्कार करने का प्रयास माना जाएगा और केवल अक्षील हमला नहीं होगा।

24. भारतीय दंड संहिता की धारा 376 और 511 के दोनों प्रावधानों के अवलोकन से पता चलता है कि, यदि मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 375 की परिभाषा के अंतर्गत आता है, तो बलात्कार के प्रयास का अपराध सिद्ध हो जाएगा।

25. आपराधिक न्यायशास्त्र का यह एक स्थापित सिद्धांत है कि प्रत्येक अपराध में, सबसे पहले, मेन्स रीया (करने का इरादा), दूसरा, अपराध करने की तैयारी और तीसरा, अपराध करने का प्रयास शामिल होता है। यदि तीसरा चरण, यानी "प्रयास" सफल हो जाता है, तो अपराध पूर्ण हो जाता है। यदि प्रयास विफल हो जाता है, तो अपराध पूर्ण नहीं होता, लेकिन फिर भी कानून उक्त कृत्य का प्रयास करने वाले व्यक्ति को दंडित करता है। "प्रयास" दंडनीय है क्योंकि अपराध के असफल होने से पहले भी मेन्स रीया, नैतिक अपराधबोध होता है और सामाजिक मूल्यों पर इसका विनाशकारी प्रभाव वास्तविक अपराध से कम नहीं होता।

26. किसी अपराध की 'तैयारी' और 'प्रयास' में एक स्पष्ट अंतर है और यह सब मामले में प्रस्तुत साक्ष्य की प्रकृति के साथ-साथ वैधानिक आदेश पर निर्भर करता है। 'तैयारी' के चरण में अपराध के लिए आवश्यक साधनों या उपायों पर विचार-विमर्श, योजना बनाना या व्यवस्था करना शामिल है। जबकि, अपराध करने का 'प्रयास'

तैयारी पूरी होने के तुरंत बाद शुरू होता है। 'प्रयास' तैयारी के बाद की गई 'मन्स रिया' का निष्पादन है। 'प्रयास' वहीं से शुरू होता है जहाँ 'तैयारी' समाप्त होती है, हालाँकि यह अपराध के वास्तविक होने से कम होता है।

27. हालाँकि, यदि विशेषताएँ स्पष्ट रूप से तैयारी के चरण से परे हैं, तो दुष्कर्म को मुख्य अपराध करने का "प्रयास" कहा जाने के योग्य माना जाएगा और ऐसा "प्रयास" अपने आप में आईपीसी की धारा 511 के मद्देनजर दंडनीय अपराध है। अपराध करने की "तैयारी" या "प्रयास" मुख्य रूप से एक अभियुक्त के कार्य और आचरण के मूल्यांकन पर निर्धारित किया जाएगा; और इस बात पर भी कि घटना "तैयारी" और "प्रयास" के बीच की पतली जगह का अतिक्रमण करती है या नहीं। यदि अपराध करने के लिए अभियुक्त पर कोई प्रत्यक्ष कार्य नहीं किया गया है और केवल प्रारंभिक अभ्यास किया गया था और यदि इस तरह की तैयारी के कृत्यों से वास्तविक अपराध के होने की संभावना का मजबूत अनुमान लगाया जाता है, तो अभियुक्त अपराध करने की तैयारी का दोषी होगा, जो दंडनीय हो भी सकता है और नहीं भी, यह दंडनीय कानूनों के इरादे और आयात पर निर्भर करता है।

28. आईपीसी की धारा 511 एक सामान्य प्रावधान है जो ऐसे अपराध करने के प्रयासों से संबंधित है जो संहिता की अन्य विशिष्ट धाराओं द्वारा दंडनीय नहीं हैं और यह अन्य बातों के साथ-साथ यह भी प्रावधान करता है कि,

“511. आजीवन कारावास या अन्य कारावास से दंडनीय अपराध करने का प्रयास करने के लिए दंड—

जो कोई इस संहिता द्वारा आजीवन कारावास या कारावास से दंडनीय अपराध करने का प्रयत्न करता है, या ऐसे अपराध कारित करने का प्रयत्न करता है, और ऐसे प्रयत्न में अपराध के किए जाने की दिशा में कोई कार्य करता है, वह, जहां ऐसे प्रयत्न के दण्ड के लिए इस संहिता द्वारा कोई स्पष्ट उपबंध नहीं किया गया है, उस अपराध के लिए उपबंधित किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि, यथास्थिति, आजीवन कारावास की आधी या उस अपराध के लिए उपबंधित कारावास की सबसे लंबी अवधि की आधी तक की हो सकेगी, या ऐसे जुर्माने से, जो उस अपराध के लिए उपबंधित है, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।”

29. इस स्तर पर भारतीय दंड संहिता की धारा 375 के तहत “बलात्कार” के अपराध के प्राथमिक घटकों को फिर से याद करना अत्यंत प्रासंगिक है, जो उस समय लागू था जब तत्काल मामले में घटना घटी थी।

375. बलात्कार - वह पुरुष "बलात्कार" करता है, जो इसमें इसके पश्चात अपवादित मामले के सिवाय, निम्नलिखित पांच में से किसी भी प्रकार की परिस्थिति में किसी स्त्री के साथ मैथुन करता है:-

पहला - उसकी इच्छा के विरुद्ध।

दूसरा - उसकी सहमति के बिना।

तीसरा - उसकी सहमति से, जब उसे मृत्यु या चोट का भय दिखाकर उसकी सहमति प्राप्त की गई हो।

चौथा - उसकी सहमति से, जब पुरुष जानता है कि वह उसका पति नहीं है, और उसकी सहमति इसलिए दी गई है क्योंकि वह मानती है कि वह कोई दूसरा पुरुष है जिससे वह विधिपूर्वक विवाहित है या स्वयं विवाहित मानती है।

पाँचवाँ: - उसकी सहमति से या उसके बिना, जब वह सोलह वर्ष से कम आयु की हो।

स्पष्टीकरण: - बलात्कार के अपराध के लिए आवश्यक यौन संभोग बनाने हेतु प्रवेश पर्याप्त है।

अपवाद: - किसी पुरुष द्वारा अपनी पत्नी के साथ, जिसकी पत्नी पंद्रह वर्ष से कम आयु की न हो, यौन संभोग बलात्कार नहीं है।

30. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मदन लाल बनाम जम्मू-कश्मीर राज्य मामले में 1997 (7) एससीसी 677 में अपनी राय दी थी कि बलात्कार की "तैयारी" और "प्रयास" के बीच अंतर करने के लिए अभियुक्त के कृत्य की गंभीरता निर्णायक होती है। न्यायालय ने इस प्रकार निर्णय दिया:

“12. किसी अपराध की तैयारी और प्रयास के बीच का अंतर मुख्यतः दृढ़ संकल्प की अधिक डिग्री में निहित है और बलात्कार के प्रयास के अपराध को साबित करने के लिए यह आवश्यक है कि अभियुक्त तैयारी के चरण से आगे बढ़ गया है। यदि कोई अभियुक्त किसी लड़की को नग्न करता है और फिर उसे ज़मीन पर सीधा लिटाकर अपने कपड़े उतारता है और फिर अपने उत्तेजित लिंग को लड़की के गुप्तांगों पर जबरदस्ती रगड़ता है, लेकिन योनि में प्रवेश नहीं करा पाता है और इस तरह रगड़ने पर स्वयं स्खलित हो जाता है, तो हमारे लिए यह मानना कठिन है कि यह आईपीसी की धारा 354 के तहत केवल हमले का मामला था, न कि आईपीसी की धारा 511 के साथ धारा 376 के तहत बलात्कार के प्रयास का। वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में अभियुक्त द्वारा बलात्कार के प्रयास का अपराध स्पष्ट रूप से स्थापित हो गया है और उच्च न्यायालय ने उसे आईपीसी की धारा 511 के साथ धारा 376 के तहत सही रूप से दोषी ठहराया है।”

31. बलात्कार के मामले में “प्रयास” और “तैयारी” के बीच अंतर को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कोप्पुला वेंकट राव बनाम आंध्र प्रदेश राज्य मामले में 2004 (3) एससीसी 602 में पुनः स्पष्ट किया था, जिसमें कहा गया था कि:

“10. किसी अपराध को करने का प्रयास एक ऐसा कार्य, या कार्यों की एक श्रृंखला है, जो अनिवार्य रूप से अपराध के होने की ओर ले जाता है, जब तक कि ऐसा कुछ न हो, जिसे कार्य करने वाले ने न तो पूर्वाभास किया हो और न ही इरादा किया हो, जो इसे रोक सके। प्रयास को एक आपराधिक डिजाइन के आंशिक निष्पादन में किया गया कार्य कहा जा सकता है, जो महज तैयारी से अधिक है, लेकिन वास्तविक परिणति से कम है, और, परिणति में विफलता को छोड़कर, मूल अपराध के सभी तत्वों को धारण करता है। दूसरे शब्दों में, प्रयास में अपराध करने का इरादा होता है, जो उसके वास्तविक कमीशन या परिणति/समापन से कम है। परिणामस्वरूप इसे इस रूप में परिभाषित किया जा सकता है कि यदि रोका नहीं जाता तो प्रयास किए गए कार्य की पूर्ण परिणति हो सकती थी। धारा 511 में दिए गए उदाहरण स्पष्ट रूप से महज तैयारी और प्रयास के मामलों के बीच अंतर करने के विधायी इरादे को दर्शाते हैं।

11. किसी अभियुक्त को बलात्कार के इरादे से प्रयास करने का दोषी ठहराने के लिए, अदालत को यह सुनिश्चित करना होगा कि अभियुक्त ने, जब उसने अभियोक्ता को पकड़ा था, न केवल उसके शरीर पर अपनी वासनाओं को तृप्त करना चाहा था, बल्कि वह ऐसा हर हाल में, और उसकी ओर से किसी भी प्रतिरोध के बावजूद, करना चाहता था। अभद्र हमलों को अक्सर बलात्कार के प्रयासों में बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया जाता है। इस निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए कि अभियुक्त का आचरण हर हाल में, और हर प्रतिरोध के बावजूद, अपनी वासनाओं को तृप्त करने के दृढ़ संकल्प का संकेत था, साक्ष्य मौजूद होने चाहिए। आसपास की परिस्थितियाँ कई बार इस पहलू पर प्रकाश डालती हैं।

32. अपीलकर्ता द्वारा जानबूझकर नाबालिग पीड़िता को अपने कमरे में बुलाकर उसे बिस्तर पर लिटाकर उसके और अपने कपड़े उतारकर उसके गुप्तांगों में अपना गुप्तांग डालकर वीर्यपात करने के स्पष्ट कदमों को साबित करने के लिए रिकॉर्ड में भारी सबूत मौजूद हैं। चूँकि बच्ची दर्द से कराह रही थी, इसलिए अपीलकर्ता अपने अंतिम कृत्य में सफल नहीं हो सका और वास्तविक प्रवेश से बच निकला। अगर अपीलकर्ता आंशिक रूप से भी प्रवेश करने में सफल हो जाता, तो उसका कृत्य भारतीय दंड संहिता की धारा 375 के तहत परिभाषित “बलात्कार” की परिभाषा के अंतर्गत आता।

33. अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य दर्शाते हैं कि अपीलकर्ता ने पीड़िता के गुप्तांगों में अपने गुप्तांग दबाकर उसके साथ छेड़छाड़ की और जब वह दर्द से चीखी तो उसने वीर्यपात कर दिया। एफएसएल रिपोर्ट एक्स-पी10 के अनुसार, अभिलेख पर एक ठोस साक्ष्य उपलब्ध है कि पीड़िता और अपीलकर्ता के शरीर के कुछ हिस्सों और कपड़ों पर वीर्य पाया गया था। इस प्रकार, अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि अपीलकर्ता ने

पीड़िता के साथ बलात्कार करने की अपनी दुष्ट इच्छा को पूरा करने के लिए वह सब कुछ किया जो आवश्यक था, जब वह दर्द से चीखी और उसका वीर्यपात हो गया। इसलिए, यह बलात्कार के प्रयास का एक स्पष्ट मामला है।

V. निष्कर्ष:

34. उपर्युक्त चर्चा के अनुसार, इस न्यायालय को विचारण न्यायालय के सुविचारित और सुविचारित निर्णय में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं मिलता है और इसलिए, उपरोक्त कारणों से, इस न्यायालय को इस अपील में कोई योग्यता नहीं दिखती। विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि और दण्ड के आक्षेपित निर्णय को बरकरार रखा जाता है और तदनुसार अपील खारिज की जाती है।

34.1 अपीलकर्ता की ज़मानत और ज़मानत बांड रद्द किए जाते हैं। अपीलकर्ता को निर्देश दिया जाता है कि वह दो सप्ताह के भीतर निचली अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण करे और निचली अदालत द्वारा दी गई अपनी शेष सज़ा काट ले। यदि अपीलकर्ता उपरोक्त निर्धारित समय सीमा के भीतर आत्मसमर्पण करने में विफल रहता है, तो निचली अदालत को निर्देश दिया जाता है कि वह संबंधित पुलिस अधिकारियों को अभियुक्त अपीलकर्ता को गिरफ्तार करने हेतु गिरफ्तारी वारंट भेजे और अनुपालन रिपोर्ट तैयार करके इस अदालत को भेजे।

34.2 आवश्यक अनुपालन के लिए रिकॉर्ड को ट्रायल कोर्ट में वापस भेजा जाए।

(अमृत्कर बंड, जे

केस 1

"अस्वीकरण- इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी अधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।"



Tarun Mehra
Advocate